आकाशवाणी शिमला

24.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1800 बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वैश्विक निवेशकों से हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवेश की संभावना तलाशने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने लंदन में इंडो–यूरोपियन बिज़नेस फोरम द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हर मौसम में दुनिया भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल होने के साथ–साथ वैश्विक व्यापार की गतिविधियों का केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प पर कार्य करते हुए इसे आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जलविद्युत व नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इन क्षेत्रों में यूरोपियन विशेषज्ञता व भारतीय आकांक्षाएं मिलकर मील पत्थर स्थापित कर सकती हैं। उन्होंने यूरोपियन निवेशकों से स्वास्थ्य, जैविक उत्पादों और सतत जीवन शैली में अवसरों को तलाशने का आह्वान भी किया। इस दौरान इंडो–यूरोपियन बिजनेस फोरम ने मुख्यमंत्री को उनके दूरदर्शी व परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए लीडरशिप एंड गवर्नेंस आवार्ड से सम्मानित किया।

जगत नेगी

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सेब सीजन के दौरान अभी तक एक करोड़ 90 लाख सेब की पेटियां मंडियों तक पहुंच चुकी हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एचपीएमसी के माध्यम से 60 हज़ार मीट्रिक टन सेब खरीदा गया है। जगत सिंह नेगी ने सेब फंसे होने के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि केवल लाहौल स्पीति में ही नोर्थ पोर्टल में सड़क बंद होने से किसानों, बागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जीएसटी सुधार– खाद्य उत्पाद

वस्तु और सेवा कर – जीएसटी सुधार अगली पीढ़ी के भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं, जो इस महीने की 22 तारीख को लागू हो चुके हैं। नए ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की पूर्व की चार–स्तरीय संरचना को सरल बनाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो–स्तरीय संरचना बना दी है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करने वाले ये सुधार लोगों को काफी राहत दे रहे हैं।

स्वास्थ्य धनराशि

प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24 करोड़ 44 लाख रूपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय से चिकित्सा सेवा को मजबूती मिलेगी और लोग भी लाभान्वित होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों मे आधुनिक तकनीक युक्त चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि मरीज़ों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े।

————————————————